दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२९० वा | बुधवार २० मे २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

मंत्री शाह को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: भारत कि सेना में परोसा जाती वाद का ज़हर,कर्नल सोफिया पर कि थी टिप्पणी

माफ़ी खारिज, एसआईटी जांच के आदेश

नई दिल्ली, १९ मई: (संवाददाता) मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता विजय शाह को सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अब भारी पड़ गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए विजय शाह की ओर से दी गई माफ़ी को खारिज कर दिया है और इसे औपचारिक और असंवेदनशील बताते हुए अस्वीकार कर दिया। अदालत ने न केवल मंत्री को फटकार लगाई, बल्कि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) के गठन का आदेश भी दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की एक वरिष्ठ और अनुभवी महिला अधिकारी हैं। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंध' के पश्चात मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई की आधिकारिक और सटीक जानकारी प्रदान की थी। उनके इस पेशेवर कर्तव्य के बाद, मंत्री विजय शाह ने उनके विरुद्ध अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसकी चौतरफा आलोचना हुई। आम जनता, सोशल मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों ने इस बयान को महिलाओं के सम्मान और सेना की निष्पक्ष छवि पर आघात माना।

अदालत की कार्यवाही:

सुनवाई के दौरान जब मंत्री के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने माफ़ी मांग ली है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उस माफ़ी को गैर-ईमानदार बताया और तीखा सवाल किया:

यह कैसी माफ़ी है? आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। आपके शब्दों का प्रभाव होता है। हम औपचारिक माफ़ी से संतुष्ट नहीं हैं। यह केवल अदालत की अवमानना का मामला नहीं है, बल्कि यह महिलाओं, सेना और सार्वजनिक मूल्यों का अपमान है।

अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आप अदालत में आकर माफ़ी मांग रहे हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

एसआईटी का गठन:

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाए, जिसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे, जिनमें से एक महिला अधिकारी होंगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सभी अधिकारी मध्य प्रदेश के बाहर से होंगे ताकि जांच निष्पक्ष हो। अदालत ने आदेश दिया कि यह एसआईटी २१ मई, मंगलवार तक गठित कर ली जाए और २८ मई २०२५ तक अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करे।

जनता की प्रतिक्रिया और विधि विशेषज्ञों की राय:

यह मामला केवल एक मंत्री की ज़बान से फिसले अपशब्दों का नहीं, बल्कि उस गहराते खतरे का संकेत है जिसमें कुछ राजनीतिक हस्तियां सेना जैसे संवैधानिक संस्थानों को भी जातिवाद या सांप्रदायिक सोच से प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। कर्नल सोफिया जैसी ईमानदार और पेशेवर अफसर को निशाना बनाना, उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाना और उनके चरित्र को विवादास्पद बनाना न सिर्फ़ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह संविधान की आत्मा के भी विरुद्ध है।

विधिक विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को महिला सम्मान, सैन्य प्रतिष्ठान की गरिमा और सार्वजनिक पदाधिकारियों की जवाबदेही के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक संदेश बताया है।

निष्कर्ष:

विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक व्यक्ति या एक बयान के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राजनीतिक वर्ग के लिए यह चेतावनी है कि वे सेना, न्यायपालिका और महिलाओं के सम्मान का सम्मान करें। यह निर्णय न्यायपालिका की गरिमा, पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट प्रतीक है।

वैद्यनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखते हुए हो विकास कार्य: मंत्री पंकजा मुंडे की सलाह

परळी वैजनाथ, १९ मई (प्रतिनिधि): उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज परळी दौरे के दौरान वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्र विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर महाराष्ट्र की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने सुझाव दिया कि वैद्यनाथ मंदिर परिसर में हो रहे विकास कार्य न केवल उच्च गुणवत्ता वाले हों, बल्कि मंदिर की पौराणिक और ऐतिहासिक गरिमा भी सुरक्षित रखी जाए।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ मंत्री पंकजा मुंडे ने प्रभु वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और मंदिर परिसर में चल रहे तीर्थक्षेत्र विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सरकारी विश्रामगृह में एक समीक्षा बैठक आयोजित की

गई, जिसमें विधायक धनंजय मुंडे, जिलाधिकारी विवेक जॉनसन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में पंकजा मुंडे ने कहा कि जब वे बीड की पालक मंत्री थीं, तब वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्र विकास योजना की नींव रखी गई थी। उस समय १३३ करोड़ रुपये की राशि इस योजना के लिए स्वीकृत की गई थी, जो बाद में बढ़ाकर २८६ करोड़ रुपये कर दी गई। इस योजना के तहत दर्शन मंडप, भक्त निवास, मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण और अन्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भक्तों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, और मंदिर की प्राचीनता और आध्यात्मिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी निर्माण कार्य किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्री पंकजा मुंडे का सुबह ८ बजे शक्तिकुंज वसाहत के हेलिपैड पर हेलिकॉप्टर द्वारा आगमन हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी और महायुती के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में भाजपा शहराध्यक्ष उमाताई समशेट्टे, तालुकाध्यक्ष राजेश गीते, बंडू निर्मल, पूर्व तालुकाध्यक्ष सतीश मुंडे, वैद्यनाथ बैंक के अध्यक्ष विनोद सामत, विजय वाकेकर, संदीप लाहोटी, महादेव इटके, गणेश कराड सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कोई भी पात्र लाभार्थी घरकुल सर्वे से वंचित न रह जाए

आ.संदीप क्षीरसागर की प्रशासन को सख्त हिदायत

बीड, १९ मई (प्रतिनिधि): प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे सेल्फ सर्वेक्षण की अवधि को ३१ मई २०२५ तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कई पात्र लाभार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण यह सर्वेक्षण करना कठिन हो रहा है। ऐसे में कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए, इसके लिए सभी ग्रामसेवकों को सख्त निर्देश दिए जाएं, ऐसी मांग बीड के विधायक संदीप क्षीरसागर ने प्रशासन से की है।

आ. क्षीरसागर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत घरकुल योजना का लाभ पात्र ग्रामीण नागरिकों को मिल सके, इसके लिए मोबाइल के माध्यम से सेल्फ सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। परंतु तकनीकी दिक्कतों और जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग इस योजना से वंचित हो रहे हैं। अनेक ग्रामीण अशिक्षित हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं, और तकनीकी ज्ञान की भी कमी है, जिससे उन्हें सर्वेक्षण करने में कठिनाई आ रही है।

इन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि ग्रामसेवक गांव के ऐसे पात्र लाभार्थियों का सर्वे स्वयं करें, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रह जाए। उन्होंने यह सख्त निर्देश जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के प्रकल्प संचालक, बीड और शिरूर (कासर) के गट विकास अधिकारियों को दिए हैं।

बीड से बाहर तक......

हर तरफ negative energy का राज है।
हर पार्टी ने नफरत को परोसा है, नई नस्ल में गुस्सा बे रहेमी अब नस नस में समा गई है ।
आसानी से पैसा कमाने के रास्ते बता दिए गए हैं , सब्र और शांति नाम के परिंदे को मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ने हि मिल कर खत्म कर दिया है।

अब ये negative energy जो हम ने हि हमारे नवजवानों में store कराई थी , उसे discharge तो होना है फिर उसके लिए उन्हें कोई article (कोई चीज)चाहिए हां इंसान कि हैसियत अब article कि कि हो गई है चाहे जंग का मैदान हो या गली का झगड़ा अब सिर्फ मार पीट और खुन ख़राबे से दिल नहीं भरता बल्कि इस काले करतुत को live video के जरिए दुनिया तक पहुंचना मर्दानगी समझी जा रही है।
इस भयानक बीमारी का ईलाज किसी डॉक्टर के पास नही बल्कि समाज का संतुलन बरकरार रखने वाले हमारे संतों साधुओं शिक्षकों और मौलवियों के पास है लेकिन हमारे नए system ने उन्हें बचे हुए परिंदों को ठिकाने लगाने कि जिम्मेदारी दे रखी है

काजी मखदूम।
संपादक दैनिक तामीर
9270574444

मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के संचालक शेख तैय्यब ने की उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात, शैक्षणिक कर्ज के लिए जमानतदार की शर्त रद्द करने की मांग

बीड, १९ मई (प्रतिनिधि): मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के संचालक तथा दैनिक सायं. बीड रिपोर्टर के संपादक शेख तैय्यब ने आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार से भेंट कर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक कर्ज योजनाओं में सुधार की मांग की। उन्होंने शैक्षणिक कर्ज के लिए आवश्यक जमानतदार की शर्त को हटाने का निवेदन भी सौंपा। इस अवसर पर शेख तैय्यब ने अपने पिछले छह महीनों के कार्यों का रिपोर्ट भी उपमुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया।

शेख तैय्यब ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के पास न तो स्थायी संपत्ति होती है और न ही चल संपत्ति, जिससे वे जमानत नहीं दे सकते। यही वजह है कि कई जरूरतमंद छात्र शैक्षणिक कर्ज से वंचित रह जाते हैं। इसलिए कर्ज के लिए रखी गई मालमत्ता धारक व नोकरदार जमानतदार की शर्त को हटाया जाए, ऐसी मांग उन्होंने की।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि छात्रों के नाम पर सीधे कर्ज दिया जाए और यदि आवश्यक हो तो उनसे एक लिखित बॉन्ड लिया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार की नयी योजना का हवाला दिया जिसमें नए उद्यमियों को कर्ज देते समय केंद्र सरकार खुद जिम्मेदारी ले रही है। उन्होंने मांग की कि इसी तर्ज पर राज्य सरकार भी अल्पसंख्यक छात्रों के कर्ज की जिम्मेदारी ले और जमानतदार की बाध्यता समाप्त करे।

शेख तैय्यब ने बताया कि महामंडल की स्थापना अल्पसंख्यक समाज के गरीबों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी। सरकार की कई योजनाएं इस अंतर्गत चलाई जा रही हैं, लेकिन जमानत की शर्त गरीब छात्रों के लिए एक बड़ी बाधा बन रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि महामंडल इस दिशा में क्रांतिकारी निर्णय लेता है तो इससे अल्पसंख्यक समाज के गरीब विद्यार्थियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति सुनिश्चित होगी।

उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज बीड जिले के दौरे पर हैं और परळी में आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर शेख तैय्यब ने उनसे मुलाकात की और यह मुद्दे उनके समक्ष रखे।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वो साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

बीड जिले के विकास के लिए बढ़ा हुआ निधि-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

जिल्हा नियोजन समिति की बैठक में ५७५ करोड़ रुपये का आराखड़ा प्रस्तुत

बीड, १९ मई (जिल्हा माहिती कार्यालय): राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिले के पालकमंत्री अजित पवार ने कहा है कि बीड जिले के सर्वांगीण विकास के लिए वे स्वयं वित्तमंत्री के रूप में अधिकतम निधि उपलब्ध करा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री पवार आज बीड में जिल्हा नियोजन समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस बैठक में वर्ष २०२५-२६ के लिए ५७५ करोड़ रुपये का नया आराखड़ा प्रस्तुत किया गया।

बैठक में पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, उपमुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव राजेश देशमुख, विभागीय आयुक्त दिलीप गावड़े, जिल्हाधिकारी विवेक जॉनसन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जीवणे और पुलिस अधीक्षक नवनीत कोवत प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

बैठक में विधायक विक्रम काळे, विधायक सतीश चव्हाण, विधायक सुरेश धस, विधायक प्रकाश सोळंके, विधायक धनंजय मुंडे, विधायक नमिता मुंदडा और विधायक विजयसिंह पंडित सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष २०२४-२५ के लिए ४८४ करोड़ रुपये का आराखड़ा तैयार किया गया था, जिसकी १००% राशि खर्च हो चुकी है। इस समीक्षा बैठक में उसका विश्लेषण भी किया गया। जिल्हाधिकारी विवेक जॉनसन ने आगामी वर्ष के लिए प्रस्तुत आराखड़े का प्रेजेंटेशन किया।

अजित पवार ने कहा कि अब से निधि सीधे जिले को नहीं दी जाएगी, बल्कि मुंबई से काम की प्रगति के अनुसार जारी की जाएगी। इस बार का ५७५ करोड़ रुपये का आराखड़ा पिछले वर्ष से १२८ करोड़ रुपये अधिक है और वर्ष २०२२-२३ की तुलना में यह दोगुना है।

उन्होने कहा कि किसी भी योजना की लागत १५ लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, और किसी भी काम को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रस्तावित स्थल की स्वामित्व जानकारी और भौगोलिक निर्देशांक (श्ररींळीविश-श्रेप-सळींविश) अनिवार्य होंगे।

इस वर्ष नियोजन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि हर काम की जगह पर जानकारी का बोर्ड अनिवार्य होगा और प्रशासनिक मंजूरी के १५ दिनों के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

वर्ष २०२५-२६ के लिए विभिन्न विभागों हेतु नियोजन निम्नानुसार किया गया है:

ग्रामीण व नागरी विकास: २१ करोड़

जिल्हा आरोग्य अधिकारी: १८.२० करोड़

जिल्हा शल्य चिकित्सक: २८.५० करोड़

स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज: २० करोड़ प्राथमिक शिक्षा: २८.५० करोड़

जलसंधारण: ३६ करोड़

महिला व बाल कल्याण: १८.३९ करोड़ ग्रामीण सड़कें: १०५ करोड़

पशुधन विकास: २२.२८ करोड़

पशुधन और पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने धवल क्रांति योजना के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य शासन, सीएसआर और नियोजन निधि से अलग विशेष निधि का प्रस्ताव रखा, जिसे बैठक में स्वीकार किया गया।

नागरी क्षेत्र विकास के लिए ६३.६६ करोड़, ऊर्जा विकास हेतु ३१ करोड़, पुलिस व जेल विभाग के लिए १६.३५ करोड़, राजस्व व आपदा प्रबंधन के लिए ७.४३ करोड़ और खेल मैदान विकास के लिए ४.२० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस बैठक के आयोजन में जिला नियोजन अधिकारी डॉ. सुधाकर चिंचाणे व उनकी टीम ने विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी ने किया।

अमेरिका में विनाशकारी तूफान ने मचाई भारी तबाही, २५ से ज़्यादा लोगों की मौत; लाखों घरों की बिजली गुल

रिपोर्ट: १९ मई २०२५, वर्जीनिया

वर्जीनिया: अमेरिका के दक्षिण-मध्य राज्यों में आए भीषण तूफान और बवंडर ने भारी तबाही मचाई है। मिसूरी, केंटकी और वर्जीनिया में आए इस जानलेवा तूफान में अब तक २५ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान के कारण सैकड़ों घर और व्यापारिक संस्थान तबाह हो गए हैं, जबकि लाखों लोग बिजली से वंचित हो गए हैं।

केंटकी में १८, मिसूरी में ७ की मौत

केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने जानकारी दी कि शुक्रवार रात आए तूफान में कम से कम १८ लोगों की मौत हुई है। वहीं, मिसूरी प्रशासन के मुताबिक वहां सात अन्य लोगों की जान गई है।

वर्जीनिया में पेड़ गिरने से दो की मौत

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्जीनिया में पेड़ गिरने की घटनाओं में दो लोगों की मौत हुई। तूफान की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह बड़े पैमाने पर जनहानि का कारण बना।

१०० से २०० घर तबाह, १०८,००० से ज़्यादा लोग बिजली से वंचित

लंदन, केंटकी की रहने वाली ३८ वर्षीय जेमी बर्न्स अपने पति और बेटे के साथ ट्रेलर होम में रह रही थीं। तूफान के दौरान वह अपनी बहन के ईंट के घर के बेसमेंट में छिपकर बचीं। उन्होंने बताया कि इस भीषण तूफान ने उनके क्षेत्र के १०० से २०० घरों को नष्ट कर दिया। ड्रोन्स द्वारा साझा की गई तस्वीरों में घरों का मलबा, टूटे कुएं और बिना शाखाओं के पेड़ दिखाई दिए। देर रात तक तीनों राज्यों में १ लाख ८ हजार से ज़्यादा लोग बिजली से वंचित थे।

मिसूरी के सेंट लुइस में पांच की मौत मिसूरी के प्रमुख शहर सेंट लुइस में भी तूफान ने कहर ढाया, जहां पांच लोगों की मौत हुई। सेंट लुइस की मेयर कारा स्पेंसर ने इसे अब तक का सबसे भीषण तूफान बताया। एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं इस तूफान को सबसे गंभीर कहूंगी। तूफान में ३८ लोग घायल हुए और लगभग ५,००० इमारतों को नुकसान पहुंचा।

चरच और निवासियों को भारी नुकसान

सेंटीनियल क्रिश्चियन चर्च के पादरी डेरेक पर्किन्स ने कहा, तूफान का इस क्षेत्र में आकर निवासियों और चर्च को इतना नुकसान पहुंचाना दिल तोड़ने वाला है। चर्च में सेवा देने वाले ब्रूस मैडिसन ने बताया कि समुदाय इस त्रासदी से उबरने के लिए एकजुट हो रहा है।

हंगामी हालात और चेतावनी के बावजूद मौतें

गंभीर मौसम की चेतावनी पहले ही जारी की गई थी। गवर्नर बेशियर ने शुक्रवार को एहतियातन आपातकाल की घोषणा की थी। हालांकि, मौतों की संख्या इस पर सवाल उठा रही है कि क्या ट्रंप प्रशासन की ओर से मौसम विभाग में की गई कटौतियों ने संकट के समय स्टाफ को कमज़ोर कर दिया। २०२४ में आए थे लगभग १८०० तूफान

वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, नेशनल वेदर सर्विस (छथ्वड) के ४,२०० कर्मचारियों में से लगभग ५०० को पिछले साल हटा दिया गया या समय से पहले रिटायर कर दिया गया। छज-- के अनुसार २००४ की तुलना में २०२४ में अमेरिका में लगभग १,८०० तूफान दर्ज किए गए थे।

मुंबईकरों को फिर मिलेगा मानसून में गड्ढों और नालियों का तोहफा-राष्ट्रवादी का आरोप: अब तक सिर्फ २५% सड़कों का कार्य पूरा

मुंबई, १९ मई - मुंबई की कुल २१२१ सड़कों में से अब तक केवल ४७९ सड़कों का ही कांक्रीटीकरण कार्य पूर्ण हुआ है, जबकि १६०० से अधिक सड़कें अब भी अधूरी और खस्ताहाल अवस्था में हैं। ऐसे में पूरा शहर खुदाई और धूल से बेहाल है, और अब मानसून के आगमन के साथ ही कीचड़ में डूबने की कगार पर खड़ा है - यह आरोप राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस (शरद पवार गुट) ने लगाया है।

मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल मातेले ने महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी द्वारा ३१ मई तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने के दिए गए निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान में बृहन्मुंबई महानगरपालिका में प्रशासक राज लागू है और जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में ठेकेदार, अधिकारी और दलालों का एक सिंडिकेट सक्रिय हो गया है। यह सिंडिकेट मलाई बांटने में जुटा है, जबकि असली काम अधर में लटका हुआ है।

एडवोकेट मातेले ने सवाल उठाया कि जब आयुक्त के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है, तो क्या भ्रष्ट ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी या फिर हमेशा की तरह श्मशान जैसी शांति बरकरार रखी जाएगी?

उन्होंने कहा कि हर साल मानसून में गड्ढों की वजह से लोगों की जान जाती है, ट्रैफिक जाम में मरीज फंसते हैं और स्कूली बच्चे कीचड़ में फिसलते हैं। क्या यह वही मुंबई है जिसे शंघाई जैसा बनाने की बात होती थी, या यह श्मशान मुंबई बन चुकी है? उन्होंने पूछा।

उन्होंने चेतावनी दी कि मुंबईवासी हर साल यह सब सहते हैं, लेकिन इस बार सहन नहीं करेंगे। अब सवाल है - क्या सच में विकास हो रहा है, या केवल मलाई बांटी जा रही है?

'सारथी' योजना की अधिछात्रवृत्ति नहीं मिलने से पीएचडी शोधार्थियों को संकट, बीड के विद्यार्थियों ने की उपमुख्यमंत्री अजित पवार से गुहार

बीड, १९ मई (प्रतिनिधि): छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे (सारथी) के माध्यम से अनुसंधानरत पीएचडी विद्यार्थियों को अधिछात्रवृत्ति, घरभाड़ा भत्ता और आकस्मिक निधि दी जाती है। हालांकि, वर्ष २०२०, २०२१ और २०२२ की बैच के पीएचडी विद्यार्थियों को वर्ष २०२४ में मिलने वाली यह सहायता राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है, जिससे राज्यभर के छात्रों को अपने शोधकार्य में गंभीर अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।

इस संदर्भ में बीड जिले के अधिछात्रवृत्ति धारक विद्यार्थियों ने राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात कर जल्द से जल्द निधि उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि उनका शोधकार्य बिना किसी वित्तीय बाधा के आगे बढ़ सके। उपमुख्यमंत्री को सौंपे गए निवेदन में यह मांग की गई कि लंबित अधिछात्रवृत्ति, घरभाड़ा भत्ता और आकस्मिक निधि तत्काल वितरित की जाए, जिससे विद्यार्थियों को राहत मिल सके। इस दौरान बीड के नेता नरेंद्र काले शोधार्थी श्रीपाद कदम, ऋषिकेश लोमटे, रामेश्वर झोडगे और जयचंद तांबूरे सहित अन्य विद्यार्थी उपस्थित थे।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com